

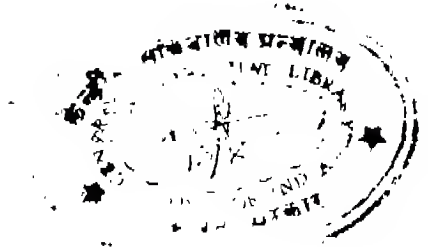


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 16]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 1994/वैशाख 30, 1916

No. 16]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 20, 1994/VAISAKHA 30, 1916

भारतीय मानक ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 1994

सं० भामाब्यूरो/का.सं./विनियम/1.—कार्यकारिणी समिति, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 38 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, भारतीय मानक ब्यूरो (सलाहकार समितियाँ) विनियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (सलाहकार समितियाँ) संशोधन विनियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय मानक ब्यूरो (सलाहकार समितियाँ) विनियम, 1987 के विनियम 3 में,—

(1) उप-विनियम (1) के खण्ड (ब) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(छ) उपभोक्ता नीति सलाहकार समिति—यह निम्नलिखित से संघटित नीति और अन्य विषयों पर सलाह देगी:—

(i) उपभोक्ता-हितों और उपभोक्ता-विचारों का समुचित रूप से ध्यान रखा जाना सुनिश्चित करने के लिए मानक निर्धारण क्रियाकलाप,

(ii) प्रमाणित चिह्न क्रियाकलाप को उपभोक्ता कल्याण के माध्यम के रूप में प्रचारित करने के उपाय और साधन,

(iii) जहाँ तक उपभोक्ता कल्याण का संबंध है, विद्यमान या नए उत्पाद या सेवा क्षेत्रों में भारतीय मानक ब्यूरो के क्रियाकलापों के द्वारा में परिवर्तन करने की आवश्यकता,

(iv) अंतरराष्ट्रीय संगठनों और उपभोक्ता निकायों जैसे उपभोक्ता नीति विषयक समिति (को पी ल को) की बैठकों में भाग लेना,

(v) भारतीय मानक ब्यूरो की, विशिष्टतया सार्वजनिक छवि में सुधार लाने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो और सामान्य उपभोक्ताओं के बीच सम्पर्क स्थापित करना,

(vi) मानक निर्धारण कार्य में उपभोक्ता संगठनों का भाग लेना,

(vii) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद से सम्पर्क करना, और

(viii) उपभोक्ता हित से सुसंगत अन्य कोई मामला,

(2) उप विनियम (2) में, खण्ड (ब) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(छ) उपभोक्ता नीति सलाहकार समिति

(i) अध्यक्ष

(ii) छह अन्य सदस्य

एन.एस. चौधरी, महानिदेशक

टिप्पणः—मूल विनियम सा. का.नि. सं. 1032 (प्र) तारीख 31 दिसम्बर, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात् सा. का. नि. सं. 1016(प्र), तारीख 17 नवम्बर, 1989 और सा. का.नि. सं. 818 (प्र), तारीख 21 अक्टूबर, 1992 द्वारा उनमें संशोधन किए गए थे।

BUREAU OF INDIAN STANDARDS NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 1994

No. BIS/EC/REG/1.—In exercise of the powers conferred by section 38 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Executive Committee, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Bureau of Indian Standards (Advisory Committees) Regulations, 1987 namely :—

1. (1) These regulations may be called the Bureau of Indian Standards (Advisory Committees) Amendment Regulations, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bureau of Indian Standards (Advisory Committees) Regulation 1987, in regulation 3,

(1) in sub-regulation (1), after clause (f), the following clause shall be inserted namely :—

“(g) Consumer Policy Advisory Committee—
It shall advise on policy and other matters relating to,

- (i) standards formulation activity to ensure that consumer interests and consumer view points are adequately taken care of;
- (ii) ways and means to propagate the Certification Marks activity as a means of consumer welfare;

(iii) on the need for changes in the structure of Bureau of Indian Standards activities in existing, or in new product or service areas in as far as consumer welfare is concerned;

(iv) participation in the meetings of international organizations and consumer bodies such as Committee on Consumer Policy (COPOLCO);

(v) communication between Bureau of Indian Standards and the common consumers especially with the objective of enhancing the public image of Bureau of Indian Standards;

(vi) participation of consumer organizations in standards formulation work;

(vii) liaison with Central Consumer Protection Council; and

(viii) any other matter of relevance to consumer interest”;

(2) in sub-regulation (2), after clause (f) the following clause shall be inserted, namely :—

“(g) Consumer Policy Advisory Committee

(i) a Chairman

(ii) six other members”

N. S. CHOUDHARY, Director General

Note : The principal regulations were published vide No. G. S. R. 1032(E) dated 31 December 1987 and subsequently amended vide GSR No. 1016(E) dated 17 November 1989 and G.S.R. No. 818(E) dated 21 October 1992.